भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4614

जिसका उत्तर 29 मार्च, 2023 को दिया जाना है ।

8 चैत्र, 1945 (शक)

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा

4614. श्री मनोज तिवारी :
डॉ. निशिकांत दुबे :
इंजीनियर गुमान सिंह दामोर :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में डिजिटल लेन-देन कर ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन डिजिटल लेन-देन के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इन बढ़ते हुए डिजिटल लेन-देन के लाभों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस सिस्टम को कब तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(ड.) सभी ग्राम पंचायतों में विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरानडिजिटल भुगतान लेनदेन ने भारत में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। डिजिटल भुगतान के आसान और सुविधाजनक तरीकेजैसे कि भारत इंटरफेस फॉर मनी-यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (भीम-यूपीआई), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) सिस्टम ने पर्याप्त वृद्धि पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है और व्यक्ति-दर-व्यक्ति (पी2पी) के साथ-साथ व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) भुगतानों को बढ़ाकर डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है। साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) जैसे पहले से मौजूद भुगतान मोड भी तेज गति से बढ़े हैं। भीम-यूपीआई उपयोगकर्ताओं के पसंदीदा भुगतान मोड के रूप में उभरा है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए डिजिटल भुगतान लेनदेन की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष (एफ़वाई)	**डिजिटल लेनदेन की कुल संख्या (करोड़ में)#**

वित्तीय वर्ष 2019-20	4,572
वित्तीय वर्ष 2020-21	5,554
वित्तीय वर्ष 2021-22	8,840
वित्तीय वर्ष 2022-23 *(23 मार्च, 2023 तक)	12,735

नोट: भीम-यूपीआई, आईएमपीएस, एनएसीएच, एईपीएस, एनईटीसी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफ़टी, आरटीजीएस, पीपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान मोड माने जाते हैं।

* अनंतिम डेटा

स्रोतः आरबीआई, एनपीसीआई और बैंक

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष में डिजिटल भुगतान का कुल मूल्य निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष (एफ़वाई)	**डिजिटल लेनदेन की कुल संख्या (करोड़ में)#**
वित्तीय वर्ष 2019-20	2,953
वित्तीय वर्ष 2020-21	3,000
वित्तीय वर्ष 2021-22	3,021
वित्तीय वर्ष 2022-23	2,812

नोट: भीम-यूपीआई, आईएमपीएस, एनएसीएच, एईपीएस, एनईटीसी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफ़टी, आरटीजीएस, पीपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान मोड माने जाते हैं।
* अनंतिम डेटा
स्रोतः आरबीआई, एनपीसीआई और बैंक

(ग): भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य बदल गया है। भारतीय उपभोक्ताओं ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रति अत्यधिक आत्मीयता प्रदर्शित की है, जिससे डिजिटल भुगतान अवसंरचना में तेजी से वृद्धि हुई है। डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लाभ इस प्रकार हैं:

(i) **भुगतान का त्वरित और सुविधाजनक तरीका**: नकदी के विपरीत, भीम-यूपीआई और आईएमपीएस जैसे डिजिटल मोड का उपयोग करके लाभार्थी के खाते में पैसा तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, भीम-यूपीआई मोड का उपयोग करके, कोई भी आसानी से याद रखने वाले ईमेल जैसे पते, जिसे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कहा जाता है, का उपयोग करके मोबाइल फोन के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को प्रभावित कर सकता है।

(ii) **वित्तीय समावेशन में वृद्धि**: डिजिटल भुगतान किसी भी समय, कहीं भी खातों तक पहुंच प्रदान करता है, इस प्रकार व्यक्तियों को अपने खातों में भुगतान प्राप्त करना और अपने फोन का उपयोग करके भुगतान करना भी आसान बनाता है। जो लोग लेन-देन के लिए बैंक आउटलेट तक भौतिक रूप से पहुंचने में लगने वाले समय, यात्रा लागत और अवसर लागत से बाधित हो सकते हैं, वे अब खाते का उपयोग करके और इस प्रक्रिया में बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बनने और बनने के विभिन्न लाभों को डिजिटल रूप से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।

(iii) **कोविड-19 महामारी के दौरान स्वीकार्यता में वृद्धि**: कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य सेवा को सक्षम बनाने में डिजिटल भुगतान के लाभों को सामने लाया है। यूपीआई क्यूआर कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) सक्षम कार्ड जैसे डिजिटल भुगतान के संपर्क रहित तरीके सामाजिक दूरी के पालन को सक्षम बनाते हैं।

(iv) **भुगतान में नवाचार को बढ़ावा देना**: भारत का स्वदेशी रूप से विकसित भीम-यूपीआई, जो मोबाइल ऐप का उपयोग करके डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है, सीधे तौर पर सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, कम-नकद समाज और वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से जुड़ा हुआ

है। भीम-यूपीआई स्मार्टफोन अपनाने, भारतीय भाषा इंटरफेस और इंटरनेट और डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच जैसे रुझानों का लाभ उठाकर अगली पीढ़ी के ऑनलाइन रीयल-टाइम भुगतान की सुविधा के लिए मानक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के एक सेट का उपयोग करता है।

(v) **एनईटीसी प्रणाली**: एनईटीसी प्रणाली ग्राहक को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करते हुए टोल पर बिना रुके एनईटीसी-सक्षम टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने में सक्षम बनाती है।

(vi) **क्यूआर कोड तकनीक को तेजी से अपनाना**: विमुद्रीकरण के बाद, क्यूआर कोड के लिए स्वीकृति बुनियादी ढांचे में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। नतीजतन, क्यूआर आधारित भुगतान तेजी से बढ़ रहे हैं। उपयोगिता बिल, ईंधन, किराना, भोजन और यात्रा के साथ-साथ विभिन्न अन्य वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने वाले व्यापारियों के भुगतान के लिए एक क्यूआर कोड को स्कैन कर सकता है।

(vii) **बेहतर गति और समय पर डिलीवरी**: नकद भुगतान के विपरीत जो अपने वाहक की गति से यात्रा करता है, डिजिटल भुगतान वस्तुतः तात्कालिक हो सकता है, भले ही प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही शहर, जिले या देश में हों।

(viii) **सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता में वृद्धि**: पहले नकद भुगतान "लीकेज" (वे भुगतान जो पूर्ण रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचते) और "घोस्ट " (नकली) प्राप्तकर्ताओं के अधीन थे, विशेष रूप से सरकारी स्थानान्तरण द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभों के संदर्भ में। अब, भुगतान के डिजिटल तरीकों के माध्यम से लाभ सीधे लक्षित लाभार्थी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।

(ix) **सुरक्षित और संरक्षित**: नकद भुगतान के प्राप्तकर्ताओं को न केवल अक्सर अपने भुगतान प्राप्त करने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है, बल्कि विशेष रूप से चोरी का भी खतरा होता है, पूरे भारत में डिजिटल भुगतान बहुत सुरक्षित हैं क्योंकि लेनदेन करने के लिए प्रमाणीकरण के कई स्तरों की आवश्यकता होती है।

(x) **भारत बिल भुगतान प्रणाली**: भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल ऐप, भीम-यूपीआई आदि जैसे कई चैनलों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एक अंतःप्रचालनीय और आसानी से सुलभ आवर्ती और बिल भुगतान सेवा प्रदान करती है।

(xi) **ऋण देना**: नकद भुगतान के विपरीत, डिजिटल भुगतान स्वचालित रूप से उपयोगकर्ता के वित्तीय पदचिह्न स्थापित करते हैं, जिससे क्रेडिट सहित औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ती है। बैंक और अन्य ऋण देने वाली संस्थाएं डिजिटल लेनदेन इतिहास का उपयोग खुदरा ऋण देने और व्यवसायों को उधार देने के लिए नकदी प्रवाह-आधारित ऋण निर्णय लेने के लिए कर सकती हैं, जिसमें छोटे व्यवसाय भी शामिल हैं, जिन्हें सत्यापन योग्य नकदी प्रवाह की अनुपस्थिति में क्रेडिट प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

(xii) **फिनटेक को बढ़ावा देना :** फिनटेक पूरे डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को लाभान्वित करने वाले पारदर्शी, सुरक्षित, तेज और लागत प्रभावी तंत्र को सक्षम करके डिजिटल लेनदेन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिनटेक ने पी2पी और पी2एम भुगतान को बढ़ाकर डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है।

(घ): एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र), इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय ने प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा और लोक शिकायत (डीएआर एंड पीजी), केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार लाइन विभागतैयार केंद्रीय सचिवालय मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर (सीएसएमओपी) के अनुसार ई-ऑफिस उत्पाद (एक डिजिटल कार्यस्थल समाधान) को डिजाइन और विकसित किया है । वर्तमान मेंकेंद्र सरकार के सभी 84 मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस शुरू किया गया है।

(ङ): भारतनेट परियोजना देश में ग्राम पंचायतों (जीपी)/गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है। यह बुनियादी ढांचा गांवों/सरकारी संस्थानों, स्कूलों और निजी क्षेत्रों सहित जीपी/ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी)/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को पट्टे पर दिया गया है। फरवरी 2023 तक, भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 189256 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है। दिनांक 30.06.2021 कोकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट को ग्राम पंचायतों से परे देश के गांवों तक विस्तारित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। भारतनेट परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2025 है।

******